भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3029

20 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 के तहत स्थापित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

3029. श्री संजय सिंह:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी), 2017 के अंतर्गत स्थापित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या कितनी है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए ऐसे एमएसएमई की राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ राज्यों के लिए संसाधन आवंटन में कमी रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने एनएसपी 2017 के अंतर्गत एमएसएमई क्षेत्र की प्रगति की कोई स्वतंत्र लेखा-परीक्षा या आकलन किया है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (ग): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार एमएसएमई सहित देश में इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित कर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। इस्पात संयंत्र स्थापित करने संबंधित निर्णय उद्योग द्वारा कच्चे माल की उपलब्धता, पत्तन से दूरी, लॉजिस्टिक आदि प्रौद्योगिकी-वाणिज्यिक सोच-विचार के आधार पर लिए जाते हैं। विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य-वार स्थापित इस्पात इकाइयों (एमएसएमई सहित) की संख्या का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है। राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी), 2017 के अनुमानों की तुलना में क्षेत्र की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:-

राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी) 2017 के अनुमान और वर्तमान स्थिति

(मिलियन टन में)

क्र.सं.	**मापदंड**	**एनएसपी, 2017 के तहत (वर्ष 2030-31 के लिए) अनुमान**	**वर्तमान स्थिति (वित्तीय वर्ष 2023-2024)**
i.	कुल कच्चा इस्पात क्षमता	300	179.51
ii.	कुल कच्चा इस्पात मांग/उत्पादन	255	144.04
iii.	कुल तैयार इस्पात मांग/उत्पादन	230	138.82
iv.	प्रति व्यक्ति तैयार इस्पात की खपत (कि.ग्रा में)	158	97.70

******

अनुलग्नक

विगत पांच वर्षों के दौरान स्थापित इस्पात इकाइयों (एमएसएमई इकाइयों सहित) की संख्या

राज्य	**इकाइयों की संख्या**
आंध्र प्रदेश	8
असम	8
छत्तीसगढ़	33
दादर नागर हवेली दमन दीव	1
गोवा	1
गुजरात	68
हरियाणा	13
हिमाचल प्रदेश	7
झारखंड	4
कर्नाटक	1
केरल	1
मध्यप्रदेश	12
महाराष्ट्र	22
मेघालय	1
ओडिशा	8
पंजाब	32
राजस्थान	8
तमिलनाडु	23
तेलंगाना	7
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	16
उत्तराखंड	9
पश्चिम बंगाल	21
कुल	**305**
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति	

******